and Smt. S.K. Hospital have paying ward beds. Smt. S.K. Hospital has 10 single beded rooms and 6 twin sharing rooms and AIIMS has 113 paying ward beds in Main Hospital, R.P Centre and CN centre. Dr. R.M.L. Hospital has a Nursing Home comprising of 50 rooms, 4 Intensive care beds and 20 beds for Maternity to which the CGHS beneficiaries, having basic pay of Rs. 2500/- and above are entitled. These are also allotted to the general public in exceptional circumstances subject to availability.

(c) The patients admitted in Nursing Home/Paying wards are provided with medical/surgical attention and necessary investigations, as required. They are provided with diet as per the advice of treating Doctor. The Room/Bed charges in AIIMS and Smt. S.K. Hospitals are as under:—

AIIMS

(a) 'A' Class Room : Rs. 900/- day

(b) 'B' Class Room : Rs. 600/- day

Smt. S.K. Hospital

(a) Single Room : Rs. 250/-

(b) Twin Sharing Room : Rs. 150/-

(d) and (e) At present no proposal is under consideration to introduce paying wards in any other Central Government Hospital.

Funds for Upgradation of Medical Colleges/Universities

967. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government provide funds for upgradation of certain departments of Universities/Medical Colleges in the country, under Centrally Sponsored Scheme;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether funds under that scheme were provided to medical institutions in Maharashtra during the last three years; if so, the details thereof, year-wise and institution-wise;

(d) whether all the Medical Colleges in the State were covered under the Scheme; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): (a) and (b) There is no such scheme.

(c) to (e) In view of reply to (a) and (b) above, do not arise.

विदेशों में इलाज कराए जाने पर होने वाला व्यय

968. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सरकारी खर्च पर विदेशों से इलाज करवाने के लिए कितने व्यक्तियों को अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) उन पर कुल कितना खर्च हुआ है;

(ग) क्या उनका इलाज भारत में संभव नहीं था;

(घ) क्या जिस विशेष बीमारी के इलाज के लिए इन्हें विदेश जाने की ऐसी अनुमति दी गई है उसी बीमारी का विदेश में इलाज करवाने के लिए अन्य अनेक व्यक्तियों को अनुमति प्रदान नहीं की गई;

(ङ) क्या सरकारी खर्च पर विदेशों में इलाज करवाने से संबंधित कोई नियम बने हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान 58 व्यक्तियों को सरकारी खर्च पर इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दी गई है। लगभग 4.16 करोड़ रु०, 3,33,803,73 अमरीकी डालर और 85563.91 यू के पौण्ड खर्च किए गए हैं।

(ग) से (च) विदेश में उपचार कराने के मामलों को केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के नियम 11 के अधीन डील किया जाता है जिसके अनुसार एक सरकारी सेवक उक्त नियमों के अधीन इस प्रयोजन के लिए गठित की गई चिकित्सा विशेषज्ञों की स्थायी समिति की सिफारिश पर विदेश में उपचार कराने के लिए पात्र है। उपचार के लिए व्यय का मापमान और पात्रता,